# राष्ट्रीय वज्ञिान प्रौद्योगकिी और नवाचार नीत-2020

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वज्ञिान और प्रौद्योगकिी वभिाग (Department of Science and Technology- DST) द्वारा अपनी वेबसाइट पर 5वीं **राष्ट्रीय वज्ञिान प्रौद्योगकिी और नवाचार नीत** (National Science Technology and Innovation Policy- STIP) का मसौदा जारी कयिा है।

- यह नीत 2013 की वज्ञिान प्रौद्योगकिी और नवाचार नीत का स्थान लेगी।

## प्रमुख बदिु:

**उद्देश्य:**

- नई नीत में उन व्यक्तयिों और संगठनों को शामलि कयिा गया है जो अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र से संबंधति हैं तथा उस पारस्थितिकि तंत्र को बढ़ावा देने में सक्षम हैं और जनिके द्वारा लघु, मध्यम तथा दीर्घकालकि मशिन मोड परयिोजनाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं।
- देश के सामाजकि-आर्थकि वकिास को प्ररति करने हेतु भारतीय वज्ञिान प्रौद्योगकिी और नवाचार पारस्थितिकि तंत्र की शक्तयिों और कमज़ोरयिों की पहचान करना एवं उनका पता लगाना, साथ ही भारतीय **STI** पारस्थितिकि तंत्र को वैश्वकि स्तर पर प्रतस्पिर्द्धी बनाना।

## महत्त्वपूर्ण प्रावधान:

**न्याय और समावेशन से संबंधति :**

- **लैंगकि समानता:**
  - नीत में प्रस्तावति है क सभी नर्णिय लेने वाले नकिायों में महलिाओं का कम-से-कम 30% प्रतनिधित्वि सुनश्चिति कयिा जाए, साथ ही लेस्बयिन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसज़ेंडर, क्यूर (LGBTQ+) समुदाय से जुड़े वैज्ञानकिों को **"स्पाउसल बेनफिटि्स**' (Spousal Benefits) प्रदान कयि जाएं।
  - LGBTQ + समुदाय को लैंगकि समानता से संबंधति सभी वार्तालापों में शामलि कयिा जाए और उनके अधकिारों की सुरक्षा तथा वज्ञिान एवं प्रौद्योगकिी क्षेत्र में उनके प्रतनिधित्वि व वचिारों को शामलि करने हेतु प्रावधान कयि जाएँ।
- **बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल:**
  - नीत में बाल-देखभाल को बनिा लैंगकि भेदभाव के और काम के घंटों को लचीला बनाने का प्रस्ताव कयिा गया है।
  - इसके अलावा मातृत्व, प्रसव और सही से बच्चे की सही ढंग से देखभाल करने के लयि माता-पिता हेतु पर्याप्त छुट्टी का प्रस्ताव कयिा गया है।
  - **सार्वजनकि रूप से वत्ति पोषति सभी अनुसंधान संस्थानों और वश्विवद्यिालयों को कर्मचारियों के बच्चों के लयि डे-केयर सेंटर स्थापति करने तथा बुजर्गों की देखभाल के लयि भी प्रावधान कयिा गया है।**
- **वकिलांगों के लयि:**
  - यह नीत वकिलांग लोगों की सहायता के लयि सभी वत्ति पोषति सार्वजनकि वैज्ञानकि संस्थानों में उनके समावेश न करने हेतु "संरचनात्मक और सांस्कृतकि परवर्तिन" का पक्षधर है।
- **अन्य संबंधति प्रावधान:**
  - चयन, पदोन्नत, पुरस्कार या अनुदान से संबंधति मामलों में आयु-संबंधी छूट के लयि 'शैक्षणकि स्तर पर आयु' को आधार बनाया जाए, न क लैंगकि आयु सीमा को।
  - एक ही वभिाग या प्रयोगशाला में कर्मचारी के तौर पर नयिुक्त होने वाले ववािहति युगल की एक साथ कार्य करने की सीमा को हटाना।
    - अभी तक शादीशुदा युगल एक ही वभिाग में कार्य नहीं कर सकते थे जसि कारण रोज़गार छोड़ने के मामले सामने आते हैं या जब कोई सहकर्मी शादी करने का फैसला करता हैं तो उसकी मर्ज़ी के बगैर उसका स्थानांतरण कर दयिा जाता है।
- **ओपन साइंस पॉलसिी (वन नेशन, वन सब्सक्रप्शिन):** सभी को वैज्ञानकि ज्ञान और डेटा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कयिा गया है जसिसे:
  - वैश्वकि स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानकि पत्रकिाओं की थोक में खरीद संभव होगी, साथ ही भारत में भी सभी तक इनकी मुफ्त पहुँच संभव होगी।

- ◦ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला स्थापित करना जो देश में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकार के डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा।

**अनुसंधान और शिक्षा:**

- यह नीति निर्माताओं को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और हितधारकों को एक साथ लाने के लिये शिक्षा अनुसंधान केंद्र (Education Research Centre) और सहयोगी अनुसंधान केंद्र (Collaborative Research Centre) स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।
- अनुसंधान और नवप्रवर्तन उत्कृष्टता फ्रेमवर्क (Research and Innovation Excellence Framework) की प्रासंगिकता का उद्देश्य हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना है।
- एक समर्पित पोर्टल सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान के आउटपुट तक पहुँच प्रदान करेगा जिसे **इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्चिव ऑफ रिसर्च (Indian Science and Technology Archive of Research)** के माध्यम से बनाया जाएगा।
- स्थानीय अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने तथा चुनिंदा क्षेत्रों जैसे- घरेलू उपकरणों, रेलवे, स्वच्छ तकनीक, रक्षा आदि में बड़े स्तर पर आयात को कम करने हेतु बुनियादी ढाँचा स्थापित करेगा।

**भारत की सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये:**

- यह नीति आने वाले दशक में भारत को शीर्ष तीन वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर स्थिति प्राप्त करने में सहायक होगी।
- प्रत्येक 5 वर्षों में पूर्णकालिक समकक्ष (Full-Time Equivalent) शोधकर्त्ताओं की संख्या, R&D पर सकल घरेलू व्यय (Gross Domestic Expenditure) और GERD पर निजी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करने में सहायक।
- एक **रणनीतिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (Strategic Technology Board)** की स्थापना करना जो सभी सामरिक सरकारी विभागों को जोड़ेगा और खरीदी जाने वाली या स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकियों की निगरानी तथा अनुशंसा करेगा।

## स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/draft-national-science-technology-and-innovation-policy-2020